

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1095] No. 1095]

नई दिल्ली, बृहस्पविवार, दिसम्बर 23, 2004/शैष 2, 1926 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2004/PAUSA 2, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1403(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर. एस. सोढी की अध्यक्षता में ''विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण'' का गठन करती है जो इस बात का न्यायनिर्णय करेगा कि क्या असम के यूनाइटेड़ लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं अथवा नहीं।

[फा. सं. 11011/45/2004-एनई-III] राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2004

S.O. 1403(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting Justice Shri R.S. Sodhi, Judge of Delhi High Court for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the United Liberation Front of Assam (ULFA) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/45/2004-NE. III] RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.